

दि कर्मिक पोस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 10, अंक : 25

(प्रति बुधवार),

इन्दौर, 22 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

बड़े शहरों तक सीमित नहीं प्रदूषण, बर्नीहाट- तालचेर में सबसे ज्यादा बुरे हैं हाल

नई दिल्ली। देश में प्रदूषण अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। साल के कुछ दिनों में तो छोटे शहरों में स्थिति कहीं ज्यादा खराब होती है। 22 जनवरी को भी कुछ ऐसा ही दर्ज किया गया, जब देश में बर्नीहाट की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। गौरतलब है कि गिरावट के बावजूद बर्नीहाट में वायु गुणवत्ता सूचकांक 392 पर बना हुआ है। वहीं कल तो वहां एक्वूआई 400 के पार पहुंच गया था।

कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति तालचेर की भी है, जो प्रदूषण के मामले में आज दूसरे स्थान पर रहा। तालचेर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 312 दर्ज किया गया। इसी तरह बैरकपुर में भी स्थिति बेहद खराब है, जहां एक्वूआई 304 दर्ज किया गया है। हालांकि गुवाहाटी-नगांव में स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन वहां भी एक्वूआई 300 के करीब दर्ज किया गया है। इन सभी शहरों की हवा में घुला जहर लोगों को बहुत ज्यादा बीमार बना देने के लिए काफी है। राजधानी दिल्ली से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो कल से प्रदूषण में गिरावट जरूर आई है, लेकिन इसके बावजूद वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 260 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली की तरह ही देश के छोटे बड़े 25 अन्य शहरों में वायु गुणवत्ता खराब दर्ज की गई है। इन शहरों में अगरतला, आसनसोल, बद्दी, बेगूसराय, भागलपुर, भीलवाड़ा, भुवनेश्वर, बूंदी, चरखी



दादरी, कटक, दिल्ली, धनबाद, दुर्गापुर, गुरुग्राम, गुवाहाटी, ग्वालियर, हावड़ा, कुंजेपुरा, मंडीदीप, नगांव, नलबाड़ी, पाली, पटना, राजमहेंद्रवरम, राजगीर, राउरकेला शामिल हैं। राहत की बात यह रही कि कल से देश में खराब हवा वाले शहरों की संख्या में करीब 26 फीसदी की गिरावट आई है।

वहीं दूसरी तरफ देश में एक बार फिर शिलांग की हवा सबसे साफ रही, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 21 दर्ज किया गया। ऐसे में यदि देश के सबसे प्रदूषित शहर बर्नीहाट की तुलना शिलांग से करें तो वहां स्थिति 18 गुणा ज्यादा खराब है। शिलांग की तरह ही देश में छोटे बड़े 12 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहतर बना हुआ है। इनमें हुबली, कांचीपुरम, मदिकेरी, मैहर, प्रयागराज, शिलांग, तिरुपति,

वाराणसी आदि शहर शामिल हैं। हालांकि कल से देखें तो देश में साफ हवा वाले शहरों की गिनती में 14 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है।

इसी तरह देश में आगरा सहित 69 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर संतोषजनक बना हुआ है। इन शहरों में पटियाला, प्रतापगढ़, पुदुचेरी, पुदुकोट्टई, रायरंगपुर, रामनगर, रामनाथपुरम, ऋषिकेश, सासाराम, सतना, सिलचर, शिवसागर, सूरत, तंजावुर, तिरुवनंतपुरम, थूथुकुडी, त्रिशूर, तिरुचिरापल्ली, उडुपी, वेल्लोर, विजयवाड़ा, वृंदावन आदि शामिल हैं। राहत की बात रही कि कल से देश में संतोषजनक हवा वाले शहरों की संख्या तीन फीसदी बढ़ी है।

कुल मिलाकर देखें तो जहां देश के महज पांच फीसदी शहरों में हवा साफ रही। वहीं दूसरी तरफ करीब 66 फीसदी शहरों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इसी तरह

29 फीसदी से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 22 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 237 में से महज 12 शहरों में हवा बेहतर (0-50 के बीच) रही। वहीं 69 शहरों में वायु गुणवत्ता संतोषजनक (51-100 के बीच) है, गौरतलब है कि 21 जनवरी 2025 को यह आंकड़ा 67 दर्ज किया गया।

दूसरे शहरों की तुलना में एक बार फिर बर्नीहाट (392) में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां आज एक्वूआई 400 के करीब पहुंच गया। वहीं कल भी बर्नीहाट में हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित थी, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 418 दर्ज किया गया था।

आंकड़ों पर गौर करें तो कल से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में 29 अंकों की गिरावट आई है। इसके

साथ ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर आज 260 पर पहुंच गया, मतलब की दिल्ली में वायु गुणवत्ता अभी भी 'खराब' बनी हुई है। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब दिल्ली में हवा जहरीली न हो। नवंबर में आठ दिन दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर दर्ज किया गया। इसी तरह दिसंबर 2024 में भी छह दिन वायु गुणवत्ता गंभीर दर्ज की गई थी। इस दौरान हवा में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा था कि वो लोगों को लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो गया था।

देखा जाए तो देश में प्रदूषण में उतार-चढ़ाव का दौर अभी भी जारी है। प्रदूषण के मामले में आज गुवाहाटी चौथे स्थान पर है, वहीं तालचेर (312) दूसरे, जबकि बैरकपुर (304) तीसरे स्थान पर है।

अन्य प्रमुख शहरों से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो फरीदाबाद में इंडेक्स 133, गाजियाबाद में 120, गुरुग्राम में 201, नोएडा में 131, ग्रेटर नोएडा में 173 पर पहुंच गया है।

इसी तरह मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 154 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के 'मध्यम' स्तर को दर्शाता है। जबकि लखनऊ में यह इंडेक्स 175, चेन्नई में 110, चंडीगढ़ में 194, हैदराबाद में 97, जयपुर में 124 और पटना में 202 दर्ज किया गया।

क्या विलुप्त हो जाएंगी मीठे पानी की एक चौथाई प्रजातियां, 200 को पहले ही खो चुके हैं हम



मुंबई। पृथ्वी के हर हिस्से में जीवन पनपता है, मीठे पाने से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र भी इससे अलग नहीं हैं। देखा जाए तो यह पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के एक फीसदी से भी कम हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जीवन के लिए बेहद मायने रखते हैं।

हालांकि जिस तरह इस बेहद नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो रहा है, वो यहां पाई जाने वाली वाले जीवों को विलुप्ति की कगार पर धकेल रहा है। इस बारे में की गई एक नई रिसर्च से पता चला है कि मीठे पानी की 24 फीसदी प्रजातियों पर खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है। रिसर्च में आशंका जताई गई है कि आने वाले दशकों में मीठे पानी में पाई जाने वाली मछलियों, केकड़ों और ड्रेगनफ्लाई की हजारों प्रजातियां अंतरराष्ट्रीय जर्नल नेचर में प्रकाशित अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मीठे पाने में पाई जाने वाली करीब 24,000 प्रजातियों का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं वो दर्शाते हैं कि इनमें से करीब एक-चौथाई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। करीब एक हजार प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह समस्या अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को पूरी तरह समझने के लिए अभी भी पर्याप्त जानकारी का आभाव है। अध्ययन से जुड़ी प्रमुख शोधकर्ता कैथरीन सेयर ने इन जानवरों के बारे में और अधिक जानने और इन्हें बचाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। अध्ययन से जुड़ी प्रमुख शोधकर्ता कैथरीन सेयर ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है, मीठे पानी की जैव विविधता पर आंकड़ों की कमी को कुछ न करने का बहाना नहीं बना सकते। मीठे पानी के यह इकोसिस्टम सभी ज्ञात प्रजातियों में से 10 फीसदी का घर हैं। यह न केवल लोगों को साफ पानी और जीविका प्रदान करते हैं साथ ही बाढ़ और जलवायु में आते बदलावों जैसे खतरों से

निपटने के लिए भी बेहद मायने रखते हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा प्रकृति और लोगों दोनों के लिए जरूरी है। जहां एक तरफ साफ, ताजा पानी जीवन के लिए बेहद जरूरी है। वहीं भोजन, पानी और अन्य संसाधनों की बढ़ती मांग के चलते मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है।

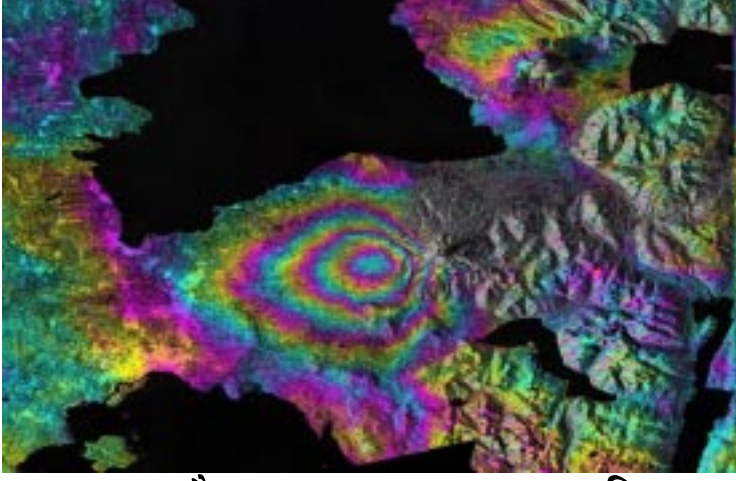
अध्ययन के मुताबिक दलदल, मैंग्रोव जैसी आर्द्रभूमियां इन नुकसानों का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगत रही हैं। 1700 के बाद से दुनिया में इन आर्द्रभूमियों का करीब 34 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्सा नष्ट हो चुका है, जो आकार में भारत जितना बड़ा है। इन आर्द्रभूमि के नष्ट होने से वहां पाए जाने वाले पौधों और जानवरों के अलावा अन्य चीजों पर भी असर पड़ रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन का सामना करने और बाढ़ को रोकने की क्षमता भी कमजोर होती है। मीठे पानी के यह स्रोत कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इनमें पानी का बहुत ज्यादा दोहन, नदियों पर बनाए जा रहे बांध आदि शामिल हैं। इनकी वजह से वन्यजीवों के आवास घट रहे हैं। कोलोराडो जैसी कुछ नदियां तो अब समुद्र तक भी नहीं पहुंच पा रही। इन सिकुड़ते आवासों में रह रहे जीव सीवेज, औद्योगिक कचरे और प्लास्टिक प्रदूषण से भी जूझ रहे हैं। हालांकि इन बढ़ते खतरों के बावजूद, मीठे पानी के पर्यावरण पर महासागरों की तुलना में बहुत कम अध्ययन किया गया है। अध्ययन के मुताबिक सभी ज्ञात प्रजातियों में से 10 फीसदी मीठे पानी पर निर्भर हैं। लेकिन इस अध्ययन में चार समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो इससे निकटता से जुड़े हैं, इनमें डेकापोड्स, ओडोनेट्स, मोलस्क और मछलियां शामिल हैं। इनमें डेकापोड, केकड़े, झींगा, क्रैफिश जैसे क्रस्टेशियन जीवों का समूह है। इनमें से कई समुद्र में रहते हैं, वहीं अन्य कई दुनिया भर में नदियों और नालों में पाए जाते हैं। इनमें से करीब 30 फीसदी पर विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। अध्ययन के मुताबिक इन जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा खास तौर पर खेतों से निकलने वाला पानी है। इसकी वजह से कीटों को मरने के लिए डाला जाने वाला कीटनाशक मीठे पानी के स्रोतों तक पहुंच जाता है, जो अन्य जीवों के साथ-साथ केकड़ों और झींगों को भी नुकसान पहुंचाता है। इतना ही नहीं यह हानिकारक केमिकल्स मछलियों के लिए भी खतरा हैं। इनकी वजह से मछलियों की वृद्धि, प्रजनन क्षमता और व्यवहार प्रभावित होता है।

सिंहस्थ महाकुंभ से उज्जैन बनेगा वैश्विक धार्मिक पर्यटन गंतव्य

इंदौर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ महाकुंभ अद्भुत सामाजिक समागम है, इससे समाज की दिशा तय होती है। पहले लोग कुंभ के मेले में तय हुई दिशा को लेकर जाते थे और समाज में बदलाव के लिए काम करते थे। समय के साथ परंपराओं में बदलाव आया है, किन्तु हमें अपनी जड़ों और मूल्यों के महत्व को समझना होगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में वर्ष 2028 में आयोजित सिंहस्थ की तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का भी मानना है कि कुंभ केवल एक मेला ही नहीं, अपितु विश्व को परंपराओं के नवोन्मेष की शिक्षा व संदेश देने वाले शानदार प्रबंधन का एक अद्भुत उदाहरण है। दुनिया को इसे केस स्टडी के तौर पर अपनाना चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार सिंहस्थ महाकुंभ-2028 की तैयारियों में जुटी है, जिसमें विकास और अधोसंरचना के काम शुरू किये जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संकल्प लिया है कि सिंहस्थ-2028 में श्रद्धालुओं को क्षिप्रा नदी के निर्मल जल में ही स्नान कराया जाए और क्षिप्रा नदी में स्वच्छ एवं शुद्ध जल का प्रवाह सदा के लिये सुनिश्चित कर उसे सही अर्थों में पुण्य-सलिला और सदानिरा बनाया जाए, साथ ही पारिस्थितिकी संतुलन भी बना रहे। संकल्प की पूर्ति के लिए उज्जैन में सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी, कान्ह क्लोज डक्ट एवं हरियाखेड़ी परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं और 18 बैराज एवं स्टॉप डेम बनाए जा रहे हैं। इससे

क्षिप्रा नदी में पूरे वर्ष निर्मल जल प्रवहमान रहेगा, साथ ही उज्जैन को शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सिंहस्थ कुंभ के सफल आयोजन से उज्जैन को एक प्रमुख वैश्विक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी स्थापित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंहस्थ आयोजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागीय कार्यों को समय-सीमा में पूरा किए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी कार्यों की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा हो रही है। वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर इनकी सतत निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उज्जैन और इंदौर जिलों में निर्माण कार्य और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन के लिए टेंडर प्रक्रिया मार्च 2025 तक पूरी कर सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर सितंबर 2025 तक पूरे कर लिए जाएं। सिंहस्थ आयोजन के दौरान परिवहन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिये दूसरे संसाधनों के साथ ही रेलवे अधिकारियों के साथ सतत समन्वय के लिए एक विशेष सेल स्थापित किया जाएगा। इससे लाखों श्रद्धालुओं के लिए सिंहस्थ तक पहुंचने का मार्ग सुगम किया जा सकेगा। विशेष मार्गों का विकास भी किया जाएगा, ताकि यातायात प्रवाह का बेहतर प्रबंधन किया जा सके और पीक-ट्रैफिक के दौरान बॉटल-नैकिंग की समस्या उपस्थित न हो सके।



नासा और भारत का नया उपग्रह निसार करेगा आसमान से पृथ्वी की निगरानी

मुंबई। चिली में कैल्बुको ज्वालामुखी के 2015 में विस्फोट से पहले और बाद में ईएसए के सेंटिनल-1ए उपग्रह द्वारा लिए गए रडार के आंकड़ों का उपयोग करके भूमि विरूपण को दर्शाने वाला इंटरफेरोग्राम। ज्वालामुखी के पश्चिम में रंगीन पट्टियां भूमि के सिकुड़ने की ओर इशारा है। निसार से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी।

चिली में कैल्बुको ज्वालामुखी के 2015 में विस्फोट से पहले और बाद में ईएसए के सेंटिनल-1ए उपग्रह द्वारा लिए गए रडार के आंकड़ों का उपयोग करके भूमि विरूपण को दर्शाने वाला इंटरफेरोग्राम। ज्वालामुखी के पश्चिम में रंगीन पट्टियां भूमि के सिकुड़ने की ओर इशारा है। निसार से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी। फोटो साभार- नासा नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का नया पृथ्वी उपग्रह नासा-इसरो सिंथेटिक अपचर रडार (निसार) आगामी महीनों में प्रक्षेपित होगा, तो यह पृथ्वी की सतह के इतने विस्तृत चित्र लेगा कि उनमें दिखाया जाएगा कि जमीन और बर्फ के छोटे-छोटे टुकड़े किस तरह और कितनी मात्रा में हिल रहे हैं।

यह पृथ्वी की लगभग सभी ठोस सतहों का प्रत्येक 12 दिन में दो बार फोटो खींचेगा, तथा भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से पहले और बाद में पृथ्वी की सतह के लचीलेपन को देखेगा। यह ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों की गति पर नजर रखेगा तथा जंगलों की वृद्धि और पेड़ों के काटे जाने सहित पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले बदलावों पर नजर रखेगा। मिशन की असाधारण क्षमताएं इसके नाम में उल्लिखित तकनीक से आती हैं- सिंथेटिक अपचर रडार (एसएआर), अंतरिक्ष में उपयोग के लिए नासा द्वारा अग्रणी, एसएआर एक रडार के ऊपर से उड़ते समय लिए गए कई मापों को जोड़ता है, ताकि नीचे के दृश्य को स्पष्ट किया जा सके। चिली में कैल्बुको ज्वालामुखी के 2015 में विस्फोट से पहले और बाद में ईएसए के सेंटिनल-1ए उपग्रह द्वारा लिए गए रडार के आंकड़ों का उपयोग करके भूमि विरूपण को दर्शाने वाला इंटरफेरोग्राम। ज्वालामुखी के पश्चिम में रंगीन पट्टियां भूमि के सिकुड़ने की ओर इशारा है। निसार से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी। यह पारंपरिक रडार की तरह काम करता है, जो दूर की सतहों और वस्तुओं का पता लगाने के लिए माइक्रोवेव का उपयोग करता है, लेकिन उच्च रिज़ॉल्यूशन पर गुणों और विशेषताओं को प्रकट करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग को बढ़ाता है। एसएआर के बिना इस तरह के विवरण हासिल करने के लिए, रडार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए बहुत बड़े एंटेना की जरूरत पड़ेगी, संचालन की तो बात ही छोड़िए। तैनात होने पर 12 मीटर चौड़ा, निसार का रडार एंटीना रिफ्लेक्टर एक शहर की बस की लंबाई जितना चौड़ा है। फिर भी, पारंपरिक रडार तकनीकों का उपयोग करते हुए, मिशन के एल-बैंड उपकरण के लिए इसे 19 किलोमीटर व्यास का होना चाहिए, ताकि पृथ्वी के 10 मीटर तक के पिक्सल की छवि बनाई जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक, सिंथेटिक एपचर रडार चीजों को बहुत सटीकता से परिष्कृत करने में मदद करती है। निसार मिशन एक गतिशील प्रणाली के रूप में हमारे ग्रह के बारे में जानने के लिए एक नया क्षेत्र खोलेगा।



आयु की प्रत्येक अवस्था में बेहतर जीवन जीने का प्रमाणिक मार्ग है आयुर्वेद- मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि आयुर्वेद के माध्यम से ही सौ वर्ष जीने के लक्ष्य को साकार कर ऋजीवते शरद-शतम्भ के भाव को सिद्ध किया जा सकता है। आयुर्वेद, आयु की प्रत्येक अवस्था में बेहतर जीवन जीने का प्रमाणिक मार्ग है। परमात्मा ने प्रकृति में ही हर व्याधि के लिए औषधि दी है, इस तथ्य का सर्वाधिक ज्ञान और उसे व्यवहार में लाने की क्षमता आयुर्वेद में निहित है। वनस्पतियों की जानकारी और योग की क्षमता से व्यक्ति स्वस्थ रहने के मार्ग का अनुसरण कर सकता है। आयुर्वेद हजारों साल पुरानी परंपरा है, संपूर्ण विश्व इसका अनुसरण करने के लिए तत्पर है और भारत आयुर्वेद की विधा का राजदूत है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय ज्ञान परंपरा की इस विधा को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अगला आयुर्वेद पर्व सिंहस्थ 2028 के अवसर पर उज्जैन में करने के लिए आमंत्रण देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस पर्व की आयोजक होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को 21वें आयुर्वेद पर्व-2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन-सत्र को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 11 आयुर्वेदिक कॉलेज आरंभ किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालयों को आयुर्वेदिक, मेडिकल सहित अन्य सभी प्रकार के कोर्स संचालित करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। आयुर्वेद में पैरामेडिकल, नर्सिंग आदि कोर्सेज चलाने की व्यवस्था की जाएगी। आयुष से संबंधित क्लीनिक और नर्सिंग होम पंजीयन का कार्य आयुष विभाग को सौंपा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के समान आयुष में भी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान उज्जैन में आरंभ किया जाएगा। आयुष विभाग की ऋय नीति में आवश्यक संशोधन कर उसे सरल बनाया जाएगा। प्रदेश में आयुर्वेदिक उत्पादों की इकाई स्थापित करने पर राज्य शासन की ओर से सहयोग प्रदान किया जाएगा। उज्जैन में सिंहस्थ के लिए आयुर्वेदिक संस्थानों को भी स्थाई निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय के सुझाव पर उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक न्यायालय स्थापित करने में राज्य शासन की ओर से सहयोग पर विचार किया जाएगा। यूनानी चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई हिंदी में भी करने की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की पहचान टाइगर राज्य के रूप में है। प्रदेश वन्य प्राणियों की दृष्टि से निरंतर समृद्ध हो रहा है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, यहां से निकलने वाली नर्मदा- गुजरात को, ताप्ती- महाराष्ट्र एवं गुजरात को, चंबल-राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश को और केन-बेतवा भी उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाती है। गर्व का विषय है कि नदी जोड़ी अभियान का क्रियान्वयन देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 1 लाख 75 हजार करोड़ राशि जारी की है। आयुष, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार ने कहा कि आयुर्वेद में शोध को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक श्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आयुर्वेद में उल्लेखित औषधियों के आधार पर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए विकसित देशों के लोगों को भी प्रेरित किया है। पद्मश्री एवं पद्म भूषण श्री देवेन्द्र त्रिगुणा ने प्रदेश में पंचमढ़ी और उज्जैन जैसे स्थानों पर आयुर्वेद, योग, पंचकर्म, आदि के केंद्र विकसित करने का सुझाव रखा। वैद्य श्री मनोज नेसरी ने आयुष को तकनीक से जोड़ने की दिशा में पहल करने की आवश्यकता बताई।

जलवायु परिवर्तन से पौधों के अंकुरण में हो रहा बदलाव, बिगड़ रहा पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन

न्यूयार्क। हमारी धरती पहले से कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रही है, ऐसे में यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि इसका पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखा जाए तो जलवायु में आते इन बदलावों की वजह से पौधों और जीवों पर पड़ने वाले कुछ प्रभाव तो बेहद स्पष्ट हैं, जैसे जीवों का बढ़ता प्रवास और फूलों का समय से पहले खिलना। लेकिन इसकी वजह से कुछ बदलाव ऐसे भी हो रहे हैं जो बेहद महीन और जटिल हैं।

बढ़ते तापमान के साथ प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक घटनाओं के समय जैसे कि बीजों के अंकुरण और पौधों की वृद्धि का समय आदि में भी बदलाव आ रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि इन बदलावों के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।

होलडन फॉरेस्ट्स एंड गार्डन्स, नॉर्थवेस्टर्न और येल यूनिवर्सिटी से जुड़े शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन से पता चला है कि तापमान में होती वृद्धि कैसे अंकुरण के समय में बदलाव करके वनस्पति समुदायों को प्रभावित कर रही है। इस अध्ययन के नतीजे जर्नल इकोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक अंकुरण का समय न केवल किसी एक प्रजाति बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई बीज उपजना शुरू करता है तो उसका समय इस बात को प्रभावित करता है कि वो सूर्य के प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों के लिए कितनी अच्छी तरह प्रतिस्पर्धा करता है। कुछ पौधे गर्म तापमान के साथ जल्द समायोजित हो जाते हैं, ऐसे में वो प्रतिक्रिया स्वरूप मौसम से पहले ही जल्द



अंकुरित हो जाते हैं। वहीं अन्य प्रजातियां इन बदलावों का सामना करने के लिए उतनी तैयार नहीं होती ऐसे में उनका अंकुरण अपने सामान्य समय पर ही होता है। इसकी वजह से कुछ प्रजातियों को जो इन बदलावों को जल्द अपना लेती हैं, उन्हें इसका फायदा मिल सकता है।

ऐसे में इन प्रजातियों को हावी होने और वनस्पति समुदाय में बदलाव का मौका मिल सकता है। इसका सीधा असर इन वनस्पतियों पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है।

अपने अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इसी तथ्य को उजागर किया है कि कैसे बढ़ते तापमान के चलते बीज के अंकुरण का समय बदल जाता है, जिससे पौधों की प्रजातियों के बढ़ने का क्रम प्रभावित होता है। शोध के मुताबिक जो पौधे पहले अंकुरित होते हैं, वो कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। ऐसे में उनके और बाद में अंकुरित होने वाले पौधों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। ऐसे में समय के साथ, यह प्रभावित कर सकता है कि कौन सी प्रजातियां पनपती हैं और कौन सी घट सकती हैं। इसका सीधा असर उन जानवरों, कीड़ों और

अन्य जीवों पर पड़ता है जो इन पर निर्भर हैं।

जलवायु परिवर्तन का पादप समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने अध्ययन में एम्मा डावसन-ग्लास के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने एक नियंत्रित अध्ययन किया है।

अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने तापमान से जुड़ी दो स्थितियों का अनुकरण किया है। इस दौरान वर्तमान परिवेश और तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस के साथ पादप समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन किया गया है। इस सेटअप से शोधकर्ताओं को यह देखने का अवसर मिला कि तापमान में होने वाला बदलाव किस प्रकार बीजों के अंकुरण के समय को प्रभावित करता है।

अध्ययन का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि तापमान में होने वाली वृद्धि से कौन सी प्रजातियां पहले अंकुरित होती हैं तथा यह बदलाव वनस्पतियों के बीच पारस्परिक क्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है।

अध्ययन के नतीजे दर्शाते हैं कि गर्म परिस्थितियों में पहले अंकुरित होने वाली प्रजातियों को

बनाए रखी। यह परिवर्तनशीलता बताती है कि जलवायु परिवर्तन सभी प्रजातियों को समान रूप से प्रभावित नहीं करेगा, जिससे पादप समुदायों के लिए अप्रत्याशित भविष्य पैदा होगा।

देखा जाए तो पादप समुदाय की संरचना में आने वाला यह बदलाव समय के साथ शाकाहारी जीवों को करेगा, जो भोजन के लिए कुछ विशिष्ट पौधों पर निर्भर हैं। इसका असर इन मांसाहारी जीवों पर भी पड़ेगा जो इन शाकाहारी जीवों पर निर्भर है। इस तरह यह पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव की वजह बन सकता है।

अध्ययन से यह भी पता चलता है कि कुछ प्रजातियां मौसमी बदलावों के अनुरूप अपने समय में बदलाव कर सकती हैं, जो उनके विकास के लिए फायदेमंद होता है। यह इस बात को भी उजागर करता है कि जलवायु में आता बदलाव पहले ही पारिस्थितिकी तंत्र को नया आकार दे रहा है, जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं।

गाँवों में लगाए गए लगभग साढ़े पांच सौ शिविर

इंदौर, इंदौर जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार नागरिकों की समस्याओं के निराकरण और शासकीय सुविधाओं का लाभ देने के लिए शहर और गाँवों में लगभग साढ़े पांच सौ शिविर लगाए गए। इन शिविरों में नागरिकों से कुल 1 लाख 14 हजार 451 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1 लाख 12 हजार 459 नागरिकों के आवेदनों का सकारात्मक निराकरण किया गया है। जिले में निराकृत आवेदनों का प्रतिशत 98.30 प्रतिशत है। शेष आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान का जिले में 26 जनवरी तक क्रियान्वयन किया जाएगा। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में जिले में जनकल्याण अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। बताया गया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप जिले में 11 दिसम्बर से जनकल्याण अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में तथा शहरों में वार्डवार शिविर निर्धारित तिथियों में लगाए जा रहे हैं।